फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 74 संख्याः 74 प्रभात जयपुर, शनिवार 14 अक्टूबर, 2023 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 3.50 रु.

ARBiT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

epaper.rashtradoot.com

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

Covering Vishwanath Pratap Singh Was The Turning Point

The story gave way to a (PIL) and, eventually, this became the "first case" where an undertrial was given compensation.

Brain Is Rewired During Pregnancy

Pregnancy can lead to long-term rewiring of the female brain

मधुसूदन मिस्त्री ने फटकार लगाकर महेश जोशी व धर्मेन्द्र राठौड़ की महत्वाकांक्षा शांत की

दोनों नेता दिल्ली पहुंचे थे, अपनी टिकट की दावेदारी मजबूत करने

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर। मुख्यमंत्री गहलोत के चहेते, महेश जोशी और धर्मेन्द्र राठौड़ आज मधुसूदन मिस्त्री से मिलने व अपनी बहाली तथा टिकट की दावेदारी मजबूत करने लिए लॉबीइंग करने के लिए दिल्ली में थे।

ए.आई.सी.सी. के सूत्रों का कहना है कि, मिस्त्री जोशी से मिले और उनसे कहा कि, अपने टिकट के लिये नहीं

- मिस्त्री ने जोशी से कहा, आपका लड़का संकट में है, और गिरफ्तारी होने के कगार पर है। आप परिवार पर ध्यान दें।
- जोशी ने जवाब दिया, कि वे अपनी गल्ती के लिए माफी मांगने आये हैं।
- मिस्त्री ने प्रत्युत्तर में कहा, माफी मांगनी है तो, सोनिया गांधी से मांगें, क्योंकि उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ बगावत की थी।
- धर्मेन्द्र राठौड़ पुष्कर से टिकिट मांग रहे हैं। मिस्त्री ने राठौड़ को सलाह दी, सचिन पायलट से मिलें, क्योंकि, वे अजमेर से सांसद रह चुके हैं और अजमेर के बारे में मेरे से ज्यादा वाकिफ़ है।
- तीसरे आरोपी धारीवाल, अपने पुत्र के लिये टिकट मांग रहे हैं। राहुल गांधी शायद पुत्र को टिकट दे दें, जिससे शान्ति धारीवाल का राजनीतिक जीवन तो समाप्त हो। धारीवाल को गहलोत की राजनीतिक महत्वकांक्षा में बलि का बकरा बनना बनना पड़ रहा है।

भागें बल्कि अपने पुत्र पर ध्यान दें, जो संकट में है और गिरफ्तारी के कगार पर है। मिस्त्री स्पष्ट बोलने वाले व्यक्ति हैं तथा बोलते समय हिचकिचाते नहीं हैं।

उन्होंने महेश जोशी से कहा कि, उनका पुत्र संकट में है अत: बेहतर होगा कि वे अपने पारिवारिक जीवन को वापस ठीक करने पर ध्यान दें।

जब जोशी ने कहा कि, जो हुआ था वो उसके लिये माफी मांगने आये हैं, तो मिस्त्री ने कहा कि, वे माफी सोनिया गाँधी से मांगें क्योंकि उन्होंने बगावत उनके (सोनिया के) खिलाफ कराई थी। उन्होंने कहा कि, वे गलत जगह माफी मांग रहे हैं।

जहाँ तक धर्मेन्द्र राठौड़ का सम्बंध है, वे अजमेर जिले के पुष्कर से टिकट मांग रहे हैं। वे अशोक गहलोत के "मनी बैग" के रुप में जाने जाते हैं, तथा वे भी उन तीन में हैं, जिन्हें सोनिया गाँधी के खिलाफ 25 सितम्बर की बगावत के बाद निलम्बित किया गया था।

सूत्रों का कहना है कि, मिस्त्री ने राठौड़ से कहा, उन्हें सचिन पायलट के पास जाकर मिलना चाहिये, क्योंकि यह उनका क्षेत्र है और वे अजमेर से सांसद रहे हैं तथा वे बेहतर जानेंगे कि यहां से किसे चुनाव लड़ना चाहिये। लगता है इससे राठौड़ को उनका स्थान बता दिया गया। अनुशासन समिति रिपोर्ट में उल्लिखित तिकड़ी में तीसरे

(शेष पृष्ठ 4 पर)

रविवार को मध्य प्रदेश की सूची आयेगी

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर। मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि, कांग्रेस, विधानसभा चुनाव प्रत्याशियों की अपनी पहली लिस्ट 15 अक्टूबर तक जारी कर सकती है।

- भाजपा अभी तक कांग्रेस पर काफी ताने मार रही थी, उम्मीदवारों की सूची जारी करने में विलंब के कारण।

उन्होंने पत्रकारों को बताया कि, शुक्रवार को सैन्ट्रल इलैक्शन कमेटी ने, 230 सीटों की विधानसभा की 60

(शेष पृष्ठ 4 पर)

रिजिजू मिज़ोरम के इलैक्शन इन्चार्ज

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने शुक्रवार को, यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइन्स, किरेन रिजिजू को मिज़ोरम के आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया।

- भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने शुक्रवार को इस नियुक्ति की घोषणा की।

इसके अलावा नागालैण्ड के उपमुख्यमंत्री यानथुन्गो पैटन तथा राष्ट्रीय

(शेष पृष्ठ 4 पर)

नीतिश कुमार सरकार आरक्षण पर लगी 50 प्रतिशत की सीलिंग तोड़ने की तैयारी में?

विधानसभा के आगामी सत्र में इस निर्णय की घोषणा संभव

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर। यह एक ऐसा निर्णय है जो सत्तारूढ़ भाजपा के लिए एक बड़ी राजनीतिक चुनौती पेश कर सकता है। बिहार की नीतीश कुमार सरकार की योजना सरकारी नौकरियों में 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा को लांघने की है। इस प्रकार का निर्णय आगामी नवम्बर माह में होने जा रहे राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र में लिया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1992 के इंदिरा साहनी केस में दिए अपने एक फैसले में जहां आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत तय की थी, वहीं कई राज्य सरकारें इस सीमा को समाप्त करने के कानून पारित कर चुकी हैं।

इन राज्यों में तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना, हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश हैं। बिहार भी यदि इन राज्यों की लिस्ट में शामिल हो जाता है तो ओ.बी.सी. मुद्दे को लेकर चल रही मुहिम वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों से पूर्व गति पकड़ सकती है और इस स्थिति को भाजपा के अनुकूल नहीं माना जा रहा।

- ऐसा माना जा रहा है कि, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना, हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान व मध्यप्रदेश में ऐसा कानून पहले ही पास हो चुका है।
- गैर भाजपा दलों का मानना है कि, बिहार में यह कानून पारित होने के बाद, आरक्षण का मुद्दा फिर मुख्य चुनावी मुद्दा बन जायेगा, जैसा, कि, गैर भाजपा दल चाहते हैं।

इकोनॉमिकली वीकर सैक्शन्स (ई.डब्ल्यू.एस.) को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए संसद ने जनवरी 2019 में एक कानून लागू किया था। इस निर्णय की वजह से आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा पहले ही लांघी जा चुकी है।

बिहार सरकार के इस कानून के मसौदे में, ई.डब्ल्यू.एस. के 10 प्रतिशत कोटे से आगे आरक्षण का ओ.बी.सी. कोटा निर्धारित करने की परिकल्पना की गई है।

प्रकट रुप से, इस तरह के निर्णय का उत्तर प्रदेश और अन्य हिंदी भाषी राज्यों में एक नया असर पड़ेगा, जिससे इस जातिगत मुद्दे के वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों में एक बड़ी चुनावी प्रचार मुहिम में बदलने की संभावना है।

जातिगत सर्वे के डेटा जारी करने में अग्रणी रहने के बाद ऐसी संभावना है कि बिहार सरकार ओ.बी.सी. और खासतौर पर एक्सट्रीमली बैकवर्ड कम्युनिटीज़ (ई.बी.सीज) के कल्याण की दिशा में कई सकारात्मक कदम उठाने की घोषणा करेगी। सूत्रों ने बताया कि राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र में ऐसी घोषणाएं की जा सकती हैं।

जातिगत सर्वे का दूसरा भाग, जिसमें पिछड़ा वर्ग की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की गणना की गई है, के विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने की संभावना है। अन्य प्रस्तावों में वर्ष 2008 के बिहार लैण्ड रिफॉर्म्स कमीशन की रिपोर्ट का आधिकारिक प्रकाशन शामिल हो सकता है। इस कमीशन की अध्यक्षता

(शेष पृष्ठ 4 पर)

न्यूज़क्लिक की याचिका खारिज

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ तथा मानव संसाधन विभाग के हैड, अमित चक्रवर्ती की याचिका को अस्वीकार कर दिया, जिसमें उन्होंने, आतंक विरोधी कानून यू.ए.पी.ए. (अनलॉफुल एक्टिविटीज़ (प्रिवैन्शन) एक्ट) के तहत हुई अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। पुलिस कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए, जस्टिस तुषार राव गेडेला की एक सदस्यीय बैंच ने कहा, "दोनों याचिकाएं सुनवाई के योग्य नहीं हैं।"

- दिल्ली हाई कोर्ट में न्यूज़क्लिक के मालिक प्रबीर पुरकायस्थ व अमित चक्रवर्ती ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दायर की थी।

पुरकायस्थ व चक्रवर्ती को दिल्ली

(शेष पृष्ठ 4 पर)

पवन खेड़ा जयपुर पहुंचे, डिज़ाइन बॉक्स को बचाने

ए.आई.सी.सी. के मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा का क्या कोई वित्तीय "इन्टरैस्ट" है डिज़ाइन बॉक्स में?

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर। क्या पवन खेड़ा नरेश अरोड़ा और डिज़ाइन बॉक्स के नवीनतम रक्षक क रूप में जयपुर आये हैं?

क्या ए.आई.सी.सी. मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा स्वयं का डिमोशन कर राजस्थान के मीडिया इंचार्ज बने हैं, क्योंकि वे नरेश अरोड़ा और डिज़ाइन बॉक्स को बर्खास्त होने से बचाना चाहते हैं?

यह एक रोचक तथ्य है कि, पवन खेड़ा, अशोक गहलोत तथा नरेश अरोड़ा, दोनों के नज़दीक हैं। कहते हैं कि, राजस्थान का पी.आर. कॉन्ट्रैक्ट अरोड़ा को मिलने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है। ए.आई.सी.सी. में यह चर्चा है कि, उनके डिज़ाइन बॉक्स में व्यवसायिक हित हैं।

- राहुल गांधी डिज़ाइन बॉक्स को बदलना चाहते हैं, पर गहलोत अभी भी हथेली लगाये हैं, क्योंकि डिज़ाइन बॉक्स पार्टी का प्रचार करने में ज्यादा सक्रिय नहीं, वह केवल गहलोत को प्रोजैक्ट करने में इन्टरैस्टेड हैं।
- गहलोत की नजदीकी के कारण भी पवन खेड़ा, डिज़ाइन बॉक्स की सुरक्षा में खड़े हुए हैं।
- डोटासरा भी अब डिज़ाइन बॉक्स के खिलाफ सक्रिय हुए हैं, पर अब तक उनकी भूमिका "प्रो गहलोत" रही है इसलिए वे मजबूत विद्रोह करने की स्थिति में नहीं हैं।

राहुल गाँधी डिज़ाइन बॉक्स को बर्खास्त करना चाहते हैं, पर, अभी तक गहलोत यह कह कर टालने में लगे हैं कि, उन्हें एक और एजेन्सी तलाशनी पड़ेगी और इतने सारे धन का भुगतान तो किया भी जा चुका है, आदि आदि।

अरोड़ा गहलोत की पसन्द हैं, क्योंकि वे उनका व्यक्तिगत पी.आर. करते हैं और मुख्यमंत्री को पार्टी की कीमत पर प्रमोट करते हैं।

जहाँ तक पार्टी का संबंध है, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष, जिन्हें अरोड़ा ने अपमानित किया था व अवहेलना की

(शेष पृष्ठ 4 पर)

लंदन के फायनैन्शियल टाइम्स को आधार बनाकर अडानी के कोयला आयात को टारगेट किया कांग्रेस ने

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर। कांग्रेस ने आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर आरोप लगाया कि, वे स्वयं एवं अपने निकट मित्र अडानी के बिज़नैस ग्रुप द्वारा बड़े पैमाने पर कोयला घोटाले के जरिए की जा रही होलसेल लूट से जनता का ध्यान हटा रहे हैं।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने फायनैन्शियल टाइम्स द्वारा किए गए नए रहस्योद्घाटनों का हवाला देते हुए अडानी के विश्वासपात्रों के एक ऐसे गुप्त नैटवर्क का हवाला दिया, जो राउण्ड ट्रिपिंग (धन को एक देश से स्थानांतरित करने के बाद पुन: मूल देश में स्थानांतरित करने), मनी लॉण्डरिंग और सेबी के कानूनों के सपट उल्लंघन में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि, इन रहस्योद्घाटनों से पता चला है कि, कैसे

- इस प्रतिष्ठित अखबार की न्यूज़ रिपोर्ट के अनुसार, अडानी ने आयातित कोयले की कीमत को बढ़ा-चढ़ा कर विदेशी कम्पनियों को हजारों करोड़ का लाभ पहुंचाया।
- फिर इन कम्पनियों ने अपने मुनाफे से अडानी के शेयर खरीदे तथा शेयर की कीमत 2000 प्रतिशत बढ़ाई।

प्रधानमंत्री और उनके निकट साथी भारत के गरीब और मध्यम वर्ग को नुकसान पहुंचाकर स्वयं को और भाजपा को सम्पन्न कर रहे हैं।

रमेश ने एक बयान में कहा कि, "यह कोई प्रतिकात्मक लूट नहीं है, बल्कि यह वास्तव में करोड़ों भारतीयों के जेबों से चोरी है।"

कांग्रेस नेता ने कहा कि, इस वर्ष की शुरुआत में उनकी पार्टी ने "हम अडानी के हैं कौन" (एच.ए.एच.के.) सिरीज़ के तहत प्रधानमंत्री मोदी से उनके चहेते बिज़नैस ग्रुप के साथ उनके रिश्तों की वास्तविक प्रकृति को लेकर सौ प्रश्न पूछे थे।

जयराम रमेश ने जोर देकर कहा कि, प्रधानमंत्री उनमें से किसी का भी उत्तर देने में विफल रहे हैं। उन्होंने स्वयं और अपने निकट मित्रों द्वारा की जा रही राष्ट्रीय सम्पदा की भारी लूट से जनता का ध्यान हटाने के लिए पी.आर. स्टंट, हैडलाइन मैनेजमैंट और अलंकारिक शब्दों का सहारा लिया है।

रमेश ने कहा, सच्चाई नहीं छुपेगी। फायनैन्शियल टाइम्स अखबार में हुए ताजा रहस्योद्घाटनों ने यह दर्शा दिया है कि, डायरैक्टोरेट ऑफ रैवैन्यू इन्टैलीजैंस (डी.आर.आई.) द्वारा लगाए गए आरोप कितने विश्वसनीय हैं। डी.आर.आई. को सबूत मिले थे कि, अडानी ग्रुप कोयला आयातों की अधिक बिलिंग करके भारत के करोड़ों रूपए डकार रहा है। प्रधानमंत्री ने शायद बाद में जांच को "मैनेज" करके देश की जांच एजेंसियों को खामोश कर दिया हो, लेकिन इसके बावजूद सच्चाई सामने आ गई।

रमेश ने बताया कि, ब्रिटेन के फायनैंशियल न्यूज़ पेपर ने वर्ष 2019 और 2027 के बीच के अडानी के 3.1 मिलियन टन के 30 कोल शिपमैन्ट्स

(शेष पृष्ठ 4 पर)